

[2024] 10 एस.सी.आर. 1381 : 2024 आईएनएससी 784

पटना नगर निगम एवं अन्य

बनाम्

मेसर्स ट्राइब्रो एंड ब्यूरो एवं अन्य

(2024 का दीवानी अपील सं. 11117)

16 अक्टूबर 2024

[विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,* न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता(ओं) द्वारा विज्ञापन पर कर/शुल्क/रॉयल्टी की कोई मांग नहीं की जा सकती क्योंकि यह बिना किसी विधायी मंजूरी के किया गया है और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न, जैसा कि खंडपीठ के समक्ष था, यह है कि क्या मांग कर/लेवी के रूप में है या निगम की सीमा के भीतर होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन की अनुमति के लिए रॉयल्टी की प्रकृति में है।

हेडनोट्स

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 – धारा 431 – विज्ञापनों पर रॉयल्टी – निगम की रॉयल्टी वसूलने की शक्ति – 29.08.2005 को एक बैठक में यह निर्णय लिया गया

कि यदि कोई एजेंसी अपना विज्ञापन लगाती है, तो निगम ऐसे होर्डिंग्स पर प्रति वर्ष 1 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से रॉयल्टी वसूलेगा - इसके बाद अपीलकर्ताओं ने विज्ञापनों पर रॉयल्टी/कर की नई दरें प्रस्तुत कीं, जो प्रतिवादी के मामले में 10 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष थी, जिसे 02.11.2007 से प्रभावी किया गया - निगम के नगर आयुक्त ने सिफारिश की कि वे सभी विज्ञापनदाता जिन्होंने 02.11.2007 के आदेश के अनुसार अपना बकाया नहीं चुकाया है, उनसे निर्धारित दर से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा और इसके अलावा बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स को हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से उनकी देय राशि का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा - रॉयल्टी/शुल्क/कर के लिए मांग की गई प्रतिवादी संख्या 1 पर - प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जुर्माने की मांग के आदेश को रद्द कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया और माना कि अपीलकर्ता(ओं) द्वारा विज्ञापन पर कर/शुल्क/रॉयल्टी की कोई मांग नहीं की जा सकती क्योंकि यह बिना किसी विधायी मंजूरी के किया गया है - यथार्थता:

निर्णय: वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति में, विज्ञापन कम्पनियाँ/संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्ष 2005 में निगम को होर्डिंग/विज्ञापन लगाने के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से रॉयल्टी देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 29.08.2005 को आयोजित बैठक में विज्ञापन कम्पनियों ने निगम द्वारा मांगी गई रॉयल्टी के भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं की थी। केवल 2 विज्ञापन कम्पनियों ने, तत्काल, लेटर पेटेंट अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, जबकि, अधिकांश विज्ञापन कम्पनियों ने निगम के दिनांक 02.11.2007 के निर्णय के पश्चात 10 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान करने का अनुपालन किया। दर में संशोधन निगम के अधिकार में था। रॉयल्टी वसूलने की निगम की शक्ति में इस आधार पर

हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि यह अधिनियम या संबंधित विनियमों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि रॉयल्टी एक कर है - इसलिए अधिनियम की धारा 431 रॉयल्टी के मामले में लागू नहीं होगी, वह भी किसी समझौते/समझौते के तहत। चूंकि रॉयल्टी और कर को समान नहीं माना जा सकता - कानून में इन नामों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता, दोनों के अलग-अलग अर्थ और अर्थ हैं - जहां तक 1 रुपये प्रति वर्ग फुट से 10 रुपये प्रति वर्ग फुट तक की दर में वृद्धि का सवाल है, 1 रुपये प्रति वर्ग फुट से 10 रुपये प्रति वर्ग फुट तक की वृद्धि को चुनौती देने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए यह न्यायालय इस पहलू पर विचार करने से परहेज करता है - निगम द्वारा 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ी हुई दर का भुगतान पूर्वव्यापी नहीं किया गया था, क्योंकि इसे नवंबर, 2007 से प्रभावी किया गया था, इस न्यायालय को निगम द्वारा प्रभावी किए जाने की तिथि से ऐसी मांग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता क्योंकि इसमें कोई तत्व नहीं है। इसमें पूर्वव्यापी प्रभाव शामिल है - इसलिए, होर्डिंग/विज्ञापनों के संबंध में 10 रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क लेने के निगम के निर्णय में, जैसा कि संबंधित पक्षों को प्रासंगिक समय पर सूचित किया गया था, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - हालांकि, भुगतान न करने पर जुर्माना लगाने में हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है - ऐसा माना जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण के साथ कि निगम को विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूलने से नहीं रोका जाएगा। [पैरा 23, 24, 29, 33, 36]

विधि का सिद्धांत - कानून के गलत प्रावधान का हवाला देना:

यह तय है कि कानून के गलत प्रावधान का हवाला देना, जब संबंधित प्राधिकारी को किसी कार्य को करने के लिए अन्यथा सशक्त किया गया हो, केवल इस आधार पर कार्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। [पैरा 30]

न्याय दृष्टान्त

मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया [2024] 8

एससीआर 540: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1796 अनुसरण किया गया।

आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एमएच घासवाला [2001] अनुपूरक 4 एससीआर

303: (2002) 1 एससीसी 633; *पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी* [2003] अनुपूरक 2

एससीआर 743: (2003) 8 एससीसी 204; *भारत संघ बनाम नवीन जिंदल* [2004] 1

एससीआर 1038: (2004) 2 एससीसी 510 - लागू नहीं माना गया।

इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य [2021] 13 एससीआर

136: (2021) 10 एससीसी 165; *सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड*

बनाम उल्हासनगर नगर परिषद [1970] 3 एससीआर 854 : (1970) 1 एससीसी

582; *केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन* [2004] 1 एससीआर 1155 : (2004) 3 एससीसी

429; *एन मणि बनाम संगीता थिएटर* (2004) 12 एससीसी 278; *राम सुंदर राम*

बनाम भारत संघ [2007] 8 एससीआर 292 : 2007 (9) स्केल 197; *पी के*

पलानीसामी बनाम एन अरुमुघम [2009] 11 एससीआर 342 : (2009) 9 एससीसी

173; *मोहम्मद. शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य* [2010] 3 एससीआर 911: (2010) 4

एससीसी 653; *हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार* [2021] 8 एससीआर 320: (2021)

9 एससीसी 292; *आलोक शंकर पांडे बनाम भारत संघ* [2007] 2 एससीआर 737:

(2007) 3 एससीसी 545 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

मोजले और व्हाइटले का कानून शब्दकोश (11वां संस्करण, 1993, पृष्ठ 243); एन्सन का अनुबंध का अंग्रेजी कानून, 22वां संस्करण, पृष्ठ 174

अधिनियमों की सूची

पटना नगर निगम अधिनियम, 1951; बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007; बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914; पटना नगर निगम (विज्ञापन और इसी तरह के उपकरणों के प्रदर्शन के लिए अनुमति प्रदान करना) विनियम, 2012

कीवर्ड की सूची

कर; शुल्क; रॉयल्टी; विज्ञापन; विज्ञापन पर कर/शुल्क/रॉयल्टी की मांग; संविधान का अनुच्छेद 265; रॉयल्टी वसूलने की निगम की शक्ति; कानून के सिद्धांत; कानून के गलत प्रावधान का हवाला देना।

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11117/2024

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 26.04.2016 के निर्णय एवं आदेश से एल.पी.ए. संख्या 1391/2012

के साथ

सिविल अपील संख्या 11118/2024

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5369/2012 (पटना उच्च न्यायालय) से उत्पन्न एल.पी.ए. संख्या 1436/2012 से उत्पन्न

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

बृजेन्द्र चाहर, वरिष्ठ अधिवक्ता, रुद्रेश्वर सिंह, कौशिक पोद्दार, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

संजय सिंह, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सर्वश्री, सुश्री सोम्याश्री, रुद्रांक शिवम सिंह, सुश्री आद्या राव, डी. के. देवेश, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहु शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अक्षय सी. श्रीवास्तव, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई।
2. विलम्ब क्षमा किया गया।
3. दोनों याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।
4. चूंकि दोनों मामलों में मुद्दा एक ही है, इसलिए इन अपीलों पर सामूहिक रूप से विचार किया जा रहा है। सुविधा के लिए, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22592/2016 से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्यों पर गौर किया जा रहा है।
5. पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ (जिसे आगे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 26.04.2016 को लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1391/2012 (जिसे आगे "आक्षेपित निर्णय" कहा जाएगा) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 5108/2012 (जिसे आगे "एकल पीठ निर्णय" कहा जाएगा) में दिनांक 29.06.2012 को एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और यह माना गया है कि अपीलकर्ता(ओं) द्वारा विज्ञापन(ओं) पर कर/शुल्क/रॉयल्टी की कोई मांग नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह बिना किसी विधायी मंजूरी के किया गया है और इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 265¹ का उल्लंघन है। 1950 (जिसे आगे "संविधान" कहा जाएगा) के तहत खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि इस मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा वसूल की गई सभी

राशि, अर्थात् विज्ञापन(ओं) पर 'कर' के रूप में, संबंधित पक्षों को वापस कर दी जाए, साथ ही यह भी कि, परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता संख्या 1/पटना नगर निगम (जिसे आगे "निगम" कहा जाएगा) द्वारा कोई जुर्माना लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

प्रसंग:

6. दिनांक 29.08.2005 को अपीलार्थी संख्या 2/नगरपालिका आयुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विज्ञापन एजेंसियों (संबंधित प्रतिवादी संख्या 1) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि यदि कोई एजेंसी अपना विज्ञापन लगाती है, तो उसे निगम के प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापनों की सूची, स्थान/स्थान, आकार आदि प्रस्तुत करना होगा, तथा निगम ऐसे होर्डिंग्स पर, जो निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भूमि पर प्रदर्शित किए जाएंगे, प्रति वर्ष 1/- रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से रॉयल्टी वसूल करेगा। अपीलकर्ताओं ने 15.01.2007 को विज्ञापनों पर रॉयल्टी/कर की नई दरें प्रस्तुत कीं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स और विज्ञापनों के लिए रॉयल्टी की अलग-अलग दरें निर्धारित की गईं, प्रतिवादी के मामले में यह दरें 10 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष निर्धारित की गईं, जो 02.11.2007 से प्रभावी की गईं।
7. इस अंतराल में पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 को निरस्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) लागू किया गया, जो अधिनियम की धारा 488(1) के तहत 05.04.2007 से प्रभावी हुआ। इस प्रकार निगम ने (नए) अधिनियम के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। कार्यालय आदेश दिनांक 02.11.2007 द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत रॉयल्टी/जुर्माने की विभिन्न दरें निर्धारित की गईं तथा आदेश दिनांक 24.08.2007 से प्रभावी किया गया। निगम के नगर आयुक्त ने अनुशंसा की कि जिन विज्ञापनदाताओं ने दिनांक 02.11.2007 के आदेश के अनुसार अपना बकाया भुगतान नहीं किया है, उनसे

निर्धारित दर से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा तथा बिना अनुमति के प्रदर्शित होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों से देय राशि का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। 15.12.2010 को निगम परिषद ने प्रस्ताव संख्या 18 पारित कर उन विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण रद्द कर दिया, जिन्होंने बढ़ी हुई रॉयल्टी/शुल्क/कर का भुगतान करने में चूक की थी। ऐसा तब किया गया जब निगम के संज्ञान में आया कि कई विज्ञापन एजेंसियों ने अवैध रूप से होर्डिंग्स प्रदर्शित किए हैं, जिनमें से कुछ के पास निगम से ऐसा करने की अनुमति भी नहीं थी और उन्होंने बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया था। 11.02.2012 को अधिनियम के तहत निगम के विभिन्न प्रस्तावों/निर्णयों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 पर रॉयल्टी/शुल्क/कर के रूप में 64,50,040/- (चौसठ लाख पचास हजार चालीस रुपये) की मांग की गई। इस मांग के साथ-साथ दिनांक 02.11.2007 के कार्यालय आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंततः *‘सभी मामलों में पटना नगर निगम द्वारा दंड की मांग के आदेश को रद्द कर दिया’* और निर्देश दिया कि *‘पटना नगर निगम को इन याचिकाकर्ताओं द्वारा देय कर/रॉयल्टी/किराया को पटना नगर निगम द्वारा निर्धारित 2007 की दरों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए।’* 18.07.2012 को निगम ने प्रतिवादी संख्या 1 को एकल पीठ के फैसले के आलोक में रॉयल्टी/शुल्क/कर के रूप में 21,98,000/- (इक्कीस लाख अठ्ठानबे हजार रुपये) रुपये का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस भेजा, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने 28.01.2013 को जवाब दिया कि गलत तरीके से गणना की गई है, इसलिए एक सही मांग नोटिस भेजा जाना चाहिए। चूंकि निगम ने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं द्वारा निर्धारित रॉयल्टी/शुल्क/कर का भुगतान जारी रखा, अर्थात् 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से।

8. प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य ने, समान स्थिति में, एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील दायर की। खंडपीठ ने, आरोपित निर्णय के माध्यम से, वृद्धि को ही रद्द कर दिया, और माना कि निगम के पास अधिनियम के तहत रॉयल्टी/शुल्क/कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विनियमन तैयार करना आवश्यक था। आरोपित निर्णय में तर्क दिया गया कि ऐसे विनियमों की अनुपस्थिति में, निगम द्वारा लगाए जाने वाले कर को लगाने/लगाने/संग्रह करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। 04.07.2012 को बनाए गए विनियमों के संबंध में, जिन्हें 13.08.2012 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, खंडपीठ ने माना कि उक्त विनियम केवल लाइसेंसिंग प्रावधानों से संबंधित हैं, न कि कर प्रावधानों से। इसमें यह भी कहा गया कि जब विनियम मौन हैं और विज्ञापन पर कर के बारे में नहीं बोलते हैं, तो निगम द्वारा इसे लगाया नहीं जा सकता। इसने आगे कहा कि विज्ञापनदाताओं से निजी व्यक्तियों को विज्ञापन कर एकत्र करने के अधिकार को नीलामी-निपटान करने का निगम का निर्णय भी पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि राज्य/उसकी संस्थाएं कराधान में व्यापार नहीं कर सकती हैं। खंडपीठ का विचार था कि कर लगाना, आकलन करना और किसी भी कर की मांग करना एक संप्रभु कार्य है, जिसे निजी व्यक्तियों को नीलामी-निपटान नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ:

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 29.08.2005 को निगम ने विज्ञापन एजेन्सी/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में रॉयल्टी लगाने के संबंध में निर्णय लिया था। इस बात पर सहमति हुई थी कि विज्ञापनदाता संबंधित होर्डिंग के क्षेत्रफल के आधार पर निगम को 1 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष की दर से रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि यह मुद्दा केवल रॉयल्टी वसूलने तक ही सीमित है तथा इसमें किसी प्रकार का कर नहीं लगाया

गया है, जैसा कि एकल पीठ तथा खण्डपीठ द्वारा गलत रूप से माना गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02.11.2007 को निगम ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसके तहत रॉयल्टी की दर 1 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कर दी गई। आगे यह भी कहा गया कि 18.07.2009 को निगम (अपीलकर्ता संख्या 2 की अध्यक्षता में) और विज्ञापनदाताओं के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें पूर्वोक्त प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं हुआ था। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि चूंकि रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए वर्ष 2011 में अपीलकर्ता संख्या 2 ने विज्ञापनदाताओं से बकाया राशि पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

10. उन्होंने आगे कहा कि 15.12.2010 को निगम की आम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी चूक करने वाली विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए और इसके बाद निगम ने संबंधित विज्ञापनदाताओं से रॉयल्टी के बकाया भुगतान की मांग की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी शामिल है, जिसके मामले में यह 64,50,040/- (चौसठ लाख पचास हजार चालीस रुपये) था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि केवल इस विलम्बित चरण में, प्रतिवादी संख्या 1 ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5108/2012 को प्राथमिकता दी, जिसमें कार्यालय आदेश दिनांक 02.11.2007 के साथ-साथ 11.02.2012 की मांग सूचना को चुनौती दी गई थी।
11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक विस्तृत एवं व्यापक निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने निगम द्वारा प्रभार लगाने को सही ठहराया तथा केवल जुर्माने की मांग में हस्तक्षेप किया। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि उसके समक्ष रिट याचिकाकर्ता, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी शामिल है, अपीलकर्ता निगम द्वारा तय किए जाने वाले चार महीने के अंतराल में आसान किशतों में निगम को देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार, विद्वान

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एकल पीठ के निर्णय के अनुरूप, निगम ने प्रतिवादी संख्या 1 पर दिनांक 18.07.2012 के पत्र के तहत 21,98,000/- रुपये (इक्कीस लाख अठ्ठानवे हजार रुपये) की नई मांग उठाई। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 21.07.2012 को केवल 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) की राशि जमा की। इस समय, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 28.01.2013 को 21,98,000/- (इक्कीस लाख अठ्ठानवे हजार रुपए) की मांग पर विवाद किया था और बकाया राशि का स्व-मूल्यांकन 1,57,050/- (एक लाख सत्तावन हजार पचास रुपए) किया था और पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद, 28,767/- (अट्ठाईस हजार सात सौ सड़सठ रुपए) की तीन किस्तों में किए जाने वाले भुगतान की गणना की, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने 28.01.2013, 29.05.2013 और 28.09.2013 को ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने बताया कि 30.03.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ने उन्हीं शर्तों पर वर्ष 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 के लिए रॉयल्टी का स्व-मूल्यांकन क्रमशः रु.48,600/-, रु.48,600/- और रु.31,000/- के रूप में किया और उसे 30.03.2013, 31.03.2014 और 31.03.2015 को जमा कर दिया। यह भी कहा गया कि इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ एलपीए संख्या 1391/2012 स्थापित करके डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित फैसला आया।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि सरल और बुनियादी मुद्दा रॉयल्टी का भुगतान था, जिस पर पार्टियों ने सहमति जताई और उसे स्वीकार किया। यह कहा गया कि भुगतान भी किए गए थे, जिन्हें अब कर की मांग/लगाए जाने का रंग दिया गया है, जो कि, विद्वान वकील ने तर्क दिया, बिल्कुल भी मामला नहीं है। यह आग्रह किया गया कि एकमात्र मुद्दा, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक विचार

किया जा सकता था, वह 1 रुपये प्रति वर्ग फुट से 10 रुपये प्रति वर्ग फुट तक की वृद्धि की मात्रा के संबंध में था, लेकिन "रॉयल्टी" के शीर्ष पर लगाए गए कर को "कर लगाना" नहीं कहा जा सकता था, जैसा कि रिकॉर्ड से ही स्पष्ट है। यह भी कहा गया कि निगम द्वारा रॉयल्टी का प्रभार भी पार्टियों के बीच किए गए एक समझौते के अनुसार था, जिसे उन्होंने डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलीय कार्यवाही में स्वीकार किया था।

13. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कानून में "रॉयल्टी" और "कर" के अलग-अलग अर्थ हैं और कर के विपरीत रॉयल्टी किसी वैधानिक प्रावधान पर आधारित नहीं है, बल्कि पक्षों के बीच समझौते पर आधारित है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि कार्यालय आदेश दिनांक 02.11.2007 के तहत अधिसूचित रॉयल्टी की दर को 1 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति वर्ग फुट करने को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2012 में ही चुनौती दी गई थी। 15.01.2007 को जारी अपने विज्ञापन द्वारा, निगम ने विज्ञापनों पर रॉयल्टी की नई दरें जारी कीं, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया और 02.11.2007 से 10 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से प्रभावी बनाया गया
14. उपरोक्त के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2021) 10 एससीसी 165, प्रासंगिक पैराग्राफ 50 से 56;² सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद (1970) 1 एससीसी 582, प्रासंगिक पैराग्राफ 11,³ और; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड (1968) 2 एससीआर 366, प्रासंगिक पैराग्राफ 10 और 24⁴ पर भरोसा किया है।

प्रतिवादी(ओं) संख्या 1 द्वारा प्रस्तुतियां:

15. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित निर्णय में सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया है और यह कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सही है, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
16. यह प्रस्तुत किया गया कि खंडपीठ ने सही माना कि निगम द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि निगम द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी शक्ति प्रदान करना विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है, जो नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसी शक्ति का अभाव और इस तथ्य के साथ कि इस तरह के अधिरोपण से पहले कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, घातक होगा, क्योंकि इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, न तो कानून में प्रावधान की अनुपस्थिति में और न ही किसी प्रक्रिया को अपनाए बिना, और न ही विनियमों द्वारा स्वीकृत, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से बनाया/अनुमोदित किया गया हो।
17. इस बात पर जोर दिया गया कि अधिनियम की धारा 146⁵ के तहत विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए लाइसेंस होना चाहिए और यह उसमें बनाए गए विनियमों के अनुसार होगा।
18. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के उद्देश्य से लाइसेंस के लिए विनियम केवल 13.08.2012 को जारी किए गए थे, जबकि मांग नोटिस 11.02.2012 की तारीख का था, यानी लाइसेंस के लिए विनियम तैयार किए जाने से बहुत पहले। इस प्रकार, उनका तर्क था कि अधिनियम की धारा 146 के तहत बनाए गए विनियमों के मद्देनजर 13.08.2012 से पहले कोई शुल्क लेने की कोई शक्ति नहीं थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन के उद्देश्यों के लिए लाइसेंस का भी प्रावधान था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 147 में विज्ञापन पर कर का प्रावधान है, जिसे भी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

19. हालांकि, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 147 के साथ धारा 423 के अनुसार कर लगाने के लिए कोई विनियमन नहीं है। इसके अभाव में, निगम उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता था जैसा उसने किया।
20. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.11.2007 को कार्यालय आदेश जारी करने के लिए कानून का कोई वैधानिक समर्थन नहीं होने के कारण, ऐसे आदेश के तहत उठाई गई मांग अमान्य है क्योंकि ऐसी मांग उठाने के लिए न तो कोई समझौता है और न ही कोई वैधानिक बल है और इसके अलावा, उक्त कार्यालय आदेश किसी लाइसेंस शुल्क के बारे में नहीं बोलता है क्योंकि विनियमों को तैयार किए बिना लाइसेंस भी नहीं दिया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि किसी भी मांग की वसूली कार्यकारी आदेश द्वारा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे विधायी समर्थन न हो।
21. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चाहे ऐसे होर्डिंग्स निजी या सार्वजनिक स्थान पर हों, 10 रुपये प्रति वर्ग फुट चार्ज करना भी मनमाना और अस्थिर है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम एच घासवाला (2002) 1 एससीसी 633; पुनित राय बनाम दिनेश चौधरी (2003) 8 एससीसी 204; भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) 2 एससीसी 510, और; केरल राज्य बनाम चंद्रमोहनन (2004) 3 एससीसी 429 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

22. इस मुद्दे पर गहन विचार करने के पश्चात न्यायालय ने पाया कि आरोपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यद्यपि खंडपीठ ने कर/लेवी लगाने से संबंधित कानून पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन हम पाते हैं कि इस मुद्दे की जांच अपेक्षित तरीके से नहीं की गई। हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मांग कर/लेवी के रूप में है या निगम की सीमाओं के भीतर होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन की अनुमति के लिए

रॉयल्टी की प्रकृति में है। न्यायालय इस समय यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानून के प्रस्ताव के साथ कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि कर/लेवी लगाने की शक्ति और तौर-तरीकों के संबंध में इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों द्वारा यह तय किया गया है, जो स्पष्ट रूप से कानून द्वारा प्राधिकरण द्वारा/के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में किया जाना है।

23. वर्तमान मामले में, हालांकि, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड (उपरोक्त) में भी स्पष्ट किया गया है, विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 56 में, कई उदाहरणों पर विचार करने के बाद, कि रॉयल्टी लगाने को कर/लेवी लगाने के बराबर नहीं माना जा सकता है। अन्यथा भी, कानून अब इस बात पर निर्भर नहीं है कि पक्षों का आचरण और सहमति किसी पक्ष को पलटने और स्वीकृत निर्णय पर हमला करने से रोकती है, सिवाय इसके कि जहां अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, या अधिकार का प्रयोग कानून या तथ्य में विकृत या दुर्भावनापूर्ण है। तत्काल तथ्यात्मक सेटिंग में, विज्ञापन कंपनियों/संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्ष 2005 में होर्डिंग्स/विज्ञापन लगाने के लिए निगम को 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की रॉयल्टी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। हम ध्यान दें कि केवल 2 विज्ञापन कंपनियों ने ही हाल ही में लेटर पेटेंट अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, जबकि हमें सूचित किया गया है कि अधिकांश विज्ञापन कंपनियों ने 02.11.2007 के निगम के निर्णय के बाद 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान करने का अनुपालन किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2005 में रॉयल्टी की प्रारंभिक दर यानी 1 रुपये प्रति वर्ग फुट 29.08.2005 को सभी हितधारकों के साथ बैठक के बाद तय की गई थी। संबंधित विज्ञापन कंपनियों ने इस तरह के होर्डिंग पर प्रति वर्ष 1 रुपये प्रति वर्ग फुट रॉयल्टी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त

की थी। इसे केवल 02.11.2007 को संशोधित किया गया था, यानी 2 साल से अधिक की अवधि के बाद।

24. हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दरों में इस तरह का संशोधन निगम की शक्ति के भीतर था। हालांकि, इस स्तर पर, हम यह मानने में भी उतने ही संकोची हैं कि अधिनियम की धारा 431⁶ के तहत कथित शक्ति के प्रयोग में बढ़ी हुई रॉयल्टी वसूलने का संकल्प गलत था क्योंकि रॉयल्टी कर नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि रॉयल्टी और कर एक ही नहीं हैं। इस प्रकार, रॉयल्टी वसूलने की निगम की शक्ति में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि यह अधिनियम या संबंधित विनियमों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उक्त 'रॉयल्टी' के कर होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, अधिनियम की धारा 431, रॉयल्टी के मामले में, वह भी किसी समझौते/समझौते के तहत, तस्वीर में नहीं आएगी। जैसा कि पहले कहा गया है, रॉयल्टी और कर को समान नहीं माना जा सकता है - इन नामों का कानून में परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही अर्थ और अर्थ बिल्कुल अलग-अलग हैं। उपरोक्त कारणों से, हम इस तर्क को तर्कसंगत नहीं मान सकते कि निगम द्वारा की गई मांग एक अनिवार्य वसूली थी। इसी तरह, हम यह भी नहीं कह सकते कि मांग कर के लक्षण थे। इसका सार यह है कि 'नामकरण चाहे जो भी हो, वर्तमान मामलों में शुल्क ... विशेषाधिकार के लिए थे ... ऐसे शुल्कों का आधार सीधे तौर पर पार्टियों के बीच की व्यवस्था के अनुसार था, हालांकि, किसी भी वैधानिक साधन के लिए संदर्भित नहीं था। ... उन्हें दिए गए ऐसे लाभ या विशेषाधिकार के लिए, पार्टियों के बीच हुए समझौतों में ऐसे लाभ के लिए शुल्कों का भुगतान करने की बात कही गई थी। हमारे विचार में, ऐसे शुल्क पूरी तरह से उचित थे।'⁷

25. हमें डर है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सेवा में लाए गए निर्णय उसके मामले में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। जहां तक घासवाला (उपरोक्त) में 5 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का संबंध है, उसमें विचार के लिए जो प्रश्न उठा था वह यह था कि 'क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-बी के तहत गठित निपटान आयोग को अधिनियम की धारा 245-डी (4) के तहत निपटान के आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी के तहत देय ब्याज को कम करने या माफ करने का अधिकार है।' न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि 'आयोग धारा 245-डी के तहत समझौता करने की अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य आयकर अधिकारियों को निर्देश जारी करने की प्रशासनिक शक्ति नहीं रख सकता है। यह निर्माण का एक सामान्य नियम है कि जब कोई कानून किसी प्राधिकरण को किसी विशेष तरीके से प्रयोग करने के लिए कुछ शक्ति प्रदान करता है, तो उक्त प्राधिकरण को इसे केवल कानून में दिए गए तरीके से ही प्रयोग करना होता है।' और माना कि 'धारा 245-डी (4) और (6) के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में आयोग के पास धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी के तहत वैधानिक रूप से देय ब्याज को कम करने या माफ करने की शक्ति नहीं है, सिवाय अधिनियम की धारा 119 के तहत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के तहत राहत देने की सीमा तक।' यहां, सवाल यह है कि क्या मांग कर या रॉयल्टी थी, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह रॉयल्टी है, जो पक्षों के बीच व्यवस्था/समझौते से जुड़ी है, जो मौजूदा तथ्यों में घासवाला (उपरोक्त) को लागू नहीं करती है।
26. पुनीत राय (उपरोक्त), तीन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा तय किया गया, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक चुनाव याचिका से उत्पन्न हुआ। अपने सहमति वाले मत में, विद्वान एस. बी. सिन्हा, जे. ने कहा कि 'यदि किसी प्रथागत कानून को किसी भी उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के तहत भारत के

राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थगित किया जाना है, तो ऐसा कानून के संदर्भ में किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।' और 'इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में गलती की कि जाति के निर्धारण के उद्देश्य से, प्रतिवादी किसी भी कानून की अनुपस्थिति में 3-3-1978 के परिपत्र पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता था। ...' अंततः, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई और अपने निर्णय को पलट दिया। सहमति वाले मत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कानून की अनुपस्थिति में इसमें क्यामेसर्स ट्राइब्रो एंड ब्यूरो एवं अन्य. नहीं किया जा सकता था। फिर से, उसी कारण से कि घासवाला (उपरोक्त) तात्कालिक विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पुनीत राय (उपरोक्त) प्रतिवादी संख्या 1 की मदद नहीं करेगा।

27. नवीन जिंदल (उपरोक्त) पुनीत राय (उपरोक्त) के समान कोरम द्वारा प्रस्तुत] ने माना कि ध्वज संहिता एक कानून नहीं था। यह भी माना गया कि कार्यकारी निर्देश, जो ध्वज संहिता थी, संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ में 'कानून' नहीं थी। यह प्रस्ताव अप्रतिबंधित है, लेकिन हमारे निष्कर्षों और विश्लेषण के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 1 के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।
28. इसी तरह, चंद्रमोहनन (उपरोक्त) में, न्यायालय [तीन न्यायाधीशों की पीठ] ने पुनीत राय (उपरोक्त) और नवीन जिंदल (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि केरल राज्य द्वारा जारी सरकारी परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 13 के दायरे में 'कानून' नहीं थे। यह मुद्दा तत्काल तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में नहीं उठता है।
29. दूसरा पहलू, जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, वह है 1 रुपए प्रति वर्ग फुट से 10 रुपए प्रति वर्ग फुट तक की दर में आनुपातिकता/उचितता। पहली नज़र में यह वृद्धि दस गुना ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्तिपरक है। हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं पेश किया गया है जिससे यह संकेत मिले कि यह दर अत्यधिक या असंगत

है, जिसके लिए न्यायिक निषेधाज्ञा की आवश्यकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 29.08.2005 को आयोजित बैठक में विज्ञापन कंपनियों ने रॉयल्टी के भुगतान पर आपत्ति नहीं जताई, जैसा कि निगम ने मांगा था। इसलिए, बाद में रॉयल्टी की मात्रा/दर के सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, न कि रॉयल्टी वसूलने के निर्णय पर। वैसे भी, चूंकि हमें नहीं लगता कि 'रॉयल्टी' एक कर/लेवी थी, इसलिए निगम की कार्रवाई को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसने अधिनियम की धारा 431 को (गलत तरीके से) उद्धृत किया है, क्योंकि जब किसी कार्य को करने की शक्ति अन्यथा मौजूद हो, तो कानून के गलत प्रावधान को उद्धृत करने से संबंधित कार्य अमान्य या अवैध नहीं हो जाता। *एन मणि बनाम संगीता थिएटर (2004) 12 एससीसी 278* में तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

‘9. यह सर्वविदित है कि यदि किसी अधिकारी के पास कानून के तहत कोई शक्ति है, केवल इसलिए कि उस शक्ति का प्रयोग करते समय शक्ति के स्रोत का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है या कानून के किसी गलत प्रावधान का संदर्भ दिया गया है, तो यह अपने आप में शक्ति के प्रयोग को तब तक दोषपूर्ण नहीं बनाता है, जब तक कि शक्ति मौजूद है और कानून में उपलब्ध स्रोत से उसका पता लगाया जा सकता है।’

(जोर दिया गया)

30. *एन मणि (उपरोक्त)* के निर्णय पर दो विद्वान न्यायाधीशों ने राम सुंदर राम बनाम भारत संघ, 2007 (9) एस.सी.एल.ई. 197 में भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने दोहराया कि कानून के गलत प्रावधान का हवाला देते हुए, जब संबंधित अधिकारी को किसी कार्य को करने के लिए अन्यथा सशक्त किया जाता है, तो केवल इस आधार पर कार्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह, *एन मणि (उपरोक्त)* और राम सुंदर

राम (उपरोक्त) का संज्ञान लेते हुए, पी.के. पलानीसामी बनाम एन. अरुमुघम (2009) 9

एस.सी.सी. 173 में दो विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित राय व्यक्त की:

‘27. ... केवल इसलिए कि अपीलकर्ता द्वारा गलत प्रावधान का उल्लेख किया गया था, हमारे विचार में, यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं होगा कि आवेदन अनुरक्षणीय नहीं था या उस पर पारित आदेश अमान्य होगा। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि गलत प्रावधान का उल्लेख करना या प्रावधान का उल्लेख न करना किसी आदेश को अमान्य नहीं करता है, यदि न्यायालय और/या वैधानिक प्राधिकरण के पास इसके लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है।’

(जोर दिया गया)

31. उपरोक्त सिद्धांत को अन्य बातों के साथ-साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य (2010) 4 एससीसी 653 और हरियाणा राज्य बनाम राज कुमार (2021) 9 एससीसी 292 में भी स्वीकृति मिली।
32. प्रतिवादी संख्या 1 ने पटना नगर निगम (विज्ञापनों एवं समान उपकरणों के प्रदर्शन हेतु अनुमति प्रदान करना) विनियम, 2012 दिनांक 04.07.2012 पर जोर दिया जो की 13.08.2012 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। हम पाते हैं कि यह केवल निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर विज्ञापन एवं समान उपकरणों के प्रदर्शन हेतु अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि इन विनियमों ने निगम को रॉयल्टी मांगने का अधिकार प्रदान किया होगा, जो हमें लगता है कि पार्टियों के बीच समझौते/व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
33. एक बार फिर, पुनरावृत्ति की कीमत पर, चूंकि 1 रुपये प्रति वर्ग फुट से 10 रुपये प्रति वर्ग फुट तक की मात्रा में वृद्धि को चुनौती देने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए हम उस पहलू पर ध्यान देने से बचते हैं, जो अब बहुत पुराना हो गया है

क्योंकि यह वर्ष 2007 से संबंधित है। इस मोड़ पर, न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों का संदर्भ लेगा, जहां पैराग्राफ संख्या 19 में निम्नलिखित रुख है:

“पूर्ववर्ती पैराग्राफ और प्रस्तुतियों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई विनियमन नहीं बनाया जाता है, तब तक प्रतिवादी संख्या 1 नगर निगम को प्रति वर्ष 10 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए सहमत है। हालांकि, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत विनियमन लागू होने के बाद नगर निगम द्वारा भविष्य में उठाई जाने वाली मांगों के साथ इसे समायोज्य किया जा सकता है।”

34. उपरोक्त के संबंध में, हम केवल यह देखते हैं कि 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ी हुई दर का भुगतान निगम द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं किया गया था, क्योंकि इसे नवंबर, 2007 से प्रभावी किया गया था, अर्थात् जनवरी, 2007 में पारित प्रस्ताव के 10 महीने बाद, और इस प्रकार, हमें निगम द्वारा इसे प्रभावी किए जाने की तारीख से ऐसी मांग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता है क्योंकि इसमें पूर्वव्यापी प्रभाव का कोई तत्व शामिल नहीं है।
35. फिर भी, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि रॉयल्टी की दर में भविष्य में कोई वृद्धि, यदि कोई हो, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। इसका प्रभाव और संचालन केवल भविष्य में ही होगा।
36. तदनुसार, उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, न्यायालय पाता है कि निगम द्वारा होर्डिंग/विज्ञापन के संबंध में 10 रुपये प्रति वर्ग फुट शुल्क लेने के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि संबंधित पक्षों को प्रासंगिक समय पर सूचित किया गया था। हालांकि, भुगतान न करने पर जुर्माना लगाने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है। इस प्रकार माना जाता है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि निगम को विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने से

नहीं रोका जाएगा। जाहिर है, विलंबित भुगतान पर ब्याज एक 'दंड' नहीं होगा, बल्कि पहले की तारीख से देय राशि के विलंबित/विलंबित भुगतान के लिए 'मुआवजे' के दायरे में होगा। इस न्यायालय ने आलोक शंकर पांडे बनाम भारत संघ (2007) 3 एससीसी 545 में भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया था:

'9. यह उल्लेख किया जा सकता है कि ब्याज के बारे में गलत धारणा है। ब्याज कोई दंड या सजा नहीं है, बल्कि यह पूंजी पर सामान्य वृद्धि है। उदाहरण के लिए, अगर A को B को एक निश्चित राशि का भुगतान करना था, मान लीजिए 10 साल पहले, लेकिन वह उसे आज वह राशि देता है, तो उसने मूल राशि पर ब्याज अपने पास रख लिया है। अगर A ने 10 साल पहले B को वह राशि चुकाई होती, तो B ने उस राशि को कहीं और निवेश किया होता और उस पर ब्याज कमाया होता, लेकिन इसके बजाय A ने उस राशि को अपने पास रखा और इस अवधि के लिए उस पर ब्याज कमाया। इसलिए, इक्विटी की मांग है कि A को न केवल मूल राशि बल्कि उस पर ब्याज भी B को वापस करना चाहिए।

(जोर दिया गया)

37. इक्विटी को संतुलित करने के लिए, न्यायालय यह संकेत देगा कि निगम के संकल्प के अनुसार संबंधित प्रतिवादी संख्या 1/विज्ञापन कंपनियों और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ी हुई दर का भुगतान उस तिथि से किया जाएगा जिस तिथि को इसे संबंधित पक्षों को सार्वजनिक/संप्रेषित किया गया था, जो भी बाद में हो, 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ। निगम को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित पक्षों को देय राशि की गणना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद संबंधित पक्षों द्वारा 16 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा उन पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा तथा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई राशि, प्रश्नगत अवधि के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग

फुट से अधिक भुगतान की गई है, तो उसे निगम द्वारा संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 तथा अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित की जाने वाली अंतिम देयता में समायोजित किया जाएगा।

38. पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।
39. दोनों अपीलों का निपटारा पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

परिशिष्ट भाग:

40. हमारे द्वारा निर्णय सुरक्षित रखे जाने के पश्चात, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1796 में इस न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से हमारे उपरोक्त दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करते हुए निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:

“126. रॉयल्टी और कर के बीच प्रमुख वैचारिक अंतर हैं: (i) स्वामी खनिजों को जीतने के अधिकार को छोड़ने के लिए रॉयल्टी वसूलता है, जबकि कर संप्रभु द्वारा लगाया जाता है; (ii) रॉयल्टी किसी विशेष कार्य को करने के लिए, अर्थात् मिट्टी से खनिजों को निकालने के लिए, भुगतान की जाती है, जबकि कर आम तौर पर कानून द्वारा निर्धारित कर योग्य घटना के संबंध में लगाया जाता है;⁸ और (iii) रॉयल्टी आम तौर पर लीज डीड से प्राप्त होती है, जबकि कर कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जाता है।

XXX

128. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। एच.पी. राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड⁹ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रॉयल्टी को कर नहीं माना। इंडसिल हाइड्रो पावर और मैंगनीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य¹⁰ में बाद के निर्णय ने कर और रॉयल्टी के बीच निम्नलिखित शब्दों में अंतर को सामने लाया:

“56. इस प्रकार, अभिव्यक्ति “रॉयल्टी” को लगातार अनुदानकर्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए भुगतान किए जाने वाले

मुआवजे के रूप में समझा जाता है और आम तौर पर अनुदानकर्ता और अनुदानकर्ता के बीच किए गए समझौते में इसकी उत्पत्ति होती है। कर के विपरीत, जो करदाता को दिए गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है, रॉयल्टी पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार होगी और आम तौर पर अनुदानकर्ता को दिए गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ इसका सीधा संबंध होता है।”

XXX

130. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही कर या अधिरोपण की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं। तदनुसार, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इंडिया सीमेंट (सुप्रा)¹¹ में यह अवलोकन कि रॉयल्टी एक कर है, गलत है।

XXX

342. ... हम संदर्भ में तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित निष्कर्षों के संदर्भ में देते हैं:

ए. रॉयल्टी एक कर नहीं है। रॉयल्टी एक संविदात्मक प्रतिफल है जो खनन पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के आनंद के लिए पट्टादाता को दिया जाता है। रॉयल्टी का भुगतान करने की देयता खनन पट्टे की संविदात्मक शर्तों से उत्पन्न होती है। सरकार को किए गए भुगतान को केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि कानून में बकाया के रूप में उनकी वसूली का प्रावधान है;’

(जोर दिया गया)

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

¹¹हेडनोट्स तैयार किए गए: अंकित ज्ञान

* लेखक

1. '265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का न लगाया जाना- कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना न तो लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा।

2. '50. डब्ल्यू.बी. राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [डब्ल्यू.बी. राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एससीसी 201] में, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी.एन. राज्य [इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी.एन. राज्य (1990) 1 एससीसी 12], और निम्नानुसार कहा गया है: (केसोराम इंडस्ट्रीज केस [राज्य पश्चिम बंगाल बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एससीसी 201], एससीसी पीपी. 293-95 और 297, पैरा 59-61 और 71)

"59. सबसे पहले हम कानून की अदालतों में अक्सर उद्धृत कुछ शब्दकोशों का उल्लेख करेंगे:

शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण (खंड 37-ए, पृष्ठ 597):

"“रॉयल्टी” उत्पादन का वह हिस्सा है जो मालिक को किसी अन्य को संपत्ति का दोहन और उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आरक्षित किया जाता है। “रॉयल्टी” शब्द का अर्थ है भूमि के कब्जेदार द्वारा उनके बीच अनुबंध द्वारा अनुमत कब्जे की प्रजातियों के लिए जमींदार को दिया जाने वाला मुआवजा। “रॉयल्टी” उत्पाद या लाभ (जैसे खदान, जंगल, आदि) का एक हिस्सा है जो मालिक द्वारा किसी अन्य को उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आरक्षित किया जाता है। उसकी संपत्ति।’

स्ट्राउड के शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश (6 वां संस्करण, 2000, खंड 3, पृष्ठ 2341):

‘रॉयल्टी’ शब्द खनन पट्टों में, रेडेंडम के उस हिस्से को दर्शाता है जो परिवर्तनशील है, और यह प्राप्त खनिजों की मात्रा या पेटेंट के अनुसार बनाए गए प्रत्येक लेख पर पेटेंटधारक को सहमत भुगतान पर निर्भर करता है। अधिकार या विशेषाधिकार जिसके लिए पारिश्रमिक रॉयल्टी के रूप में देय है।’

शब्द और वाक्यांश, कानूनी रूप से परिभाषित (तीसरा संस्करण, 1990, खंड 4, पृष्ठ 112):

‘रॉयल्टी, जिस अर्थ में शब्द का उपयोग खनन पट्टों के संबंध में किया जाता है, वह पट्टाकर्ता को एक भुगतान है

जो निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम किए गए खनिज की मात्रा के अनुपात में होता है।’

व्हार्टन लॉ लेक्सिकन (14 वां संस्करण, पृष्ठ 893):

‘रॉयल्टी - पेटेंट के अनुसार बनाए गए प्रत्येक लेख पर समझौते द्वारा पेटेंटधारक को भुगतान; या किसी लेखक को उसकी पुस्तक की बेची गई प्रत्येक प्रति पर प्रकाशक द्वारा भुगतान; या खनिजों के मालिक को हर टन या अन्य भार उठाने पर उसी के अनुसार काम करने के अधिकार के लिए।’

मोजले और व्हाइटले का कानून शब्दकोश (11 वां संस्करण, 1993, पृष्ठ 243):

‘पट्टे पर दी गई संपत्ति के काम करने पर या अन्यथा अनुदान या पट्टे के लाभ पर अनुदानकर्ता या पट्टेदार को आनुपातिक भुगतान। यह शब्द विशेष रूप से खानों, पेटेंट और कॉपीराइट के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।’

प्रेम का न्यायिक शब्दकोश (1992, खंड 2, पृष्ठ 1458):

‘रॉयल्टी वे भुगतान हैं जो सरकार खनिजों, लकड़ी या सरकार से संबंधित अन्य संपत्ति के विनियोग के लिए मांग सकती है। रॉयल्टी की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हैं, कि वस्तुओं को हटाने के विशेषाधिकार के लिए किया गया भुगतान हटाए गए मात्रा के अनुपात में है, और भुगतान का आधार एक समझौता है।’

ब्लैक का कानून शब्दकोश (7 वां संस्करण, पृष्ठ 1330):

‘रॉयल्टी। - खनिज पट्टे के अनुदानकर्ता द्वारा भूमि पर खनन या ड्रिलिंग करने के पट्टेदार के अधिकार के बदले में आरक्षित अचल संपत्ति से उत्पाद या लाभ का एक हिस्सा।

खनिज रॉयल्टी। - खनिज उत्पादन से आय के हिस्से का अधिकार।’

60. डी.के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य [डी.के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य, 1986 सप एससीसी 20] में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने "किराया", "रॉयल्टी" और "मृत किराया" से निपटा और निम्नानुसार माना

: (एससीसी पृष्ठ 53-54, पैरा 38-39)

38. किराया पट्टे की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। यह पट्टेदार से पट्टाकर्ता को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरित होने वाला विचार है।

39. खनन पट्टे में आमतौर पर पट्टेदार से पट्टाकर्ता को स्थानांतरित होने वाला विचार पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का किराया (जिसे अक्सर सतह किराया कहा जाता है), मृत किराया और रॉयल्टी है। चूंकि खनन पट्टा पट्टेदार को न केवल एक साधारण पट्टे के तहत संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार देता है, बल्कि भूमि से खनिजों को निकालने और उन्हें अपने स्वयं के उपयोग या लाभ के लिए विनियोजित करने का अधिकार भी देता है, पट्टेदार को निकाले गए खनिजों के संबंध में निकाले गए खनिजों की मात्रा के अनुपात में एक निश्चित राशि का भुगतान करना आवश्यक है। इस तरह के भुगतान को "रॉयल्टी" कहा जाता है। हालाँकि, यह हो सकता है कि खदान का ठीक से काम नहीं किया गया हो, जिससे रॉयल्टी के रूप में पट्टाकर्ता को पर्याप्त रिटर्न न मिले। खदान पर काम हो या न हो, पट्टाकर्ता को नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए पट्टेदार द्वारा उसे भुगतान की जाने वाली एक निश्चित राशि

प्रदान की जाती है। इसे "मृत किराया" कहा जाता है। "मृत किराया" की गणना पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर की जाती है जबकि रॉयल्टी की गणना निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा के आधार पर की जाती है। इस प्रकार, जबकि मृत किराया पट्टाकर्ता के लिए एक निश्चित रिटर्न है, रॉयल्टी एक रिटर्न है जो निकाले गए या निकाले गए खनिजों की मात्रा के साथ बदलता रहता है। चूंकि मृत किराया और रॉयल्टी दोनों पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के संबंध में पट्टाकर्ता को एक रिटर्न हैं, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत किराया को पट्टाकर्ता को देय रॉयल्टी की न्यूनतम गारंटीकृत राशि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन इसकी गणना पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर की जाती है न कि निकाले गए या निकाले गए खनिजों की मात्रा के आधार पर।'

मूर्ति बनाम कलेक्टर, एआईआर 1965 एससी 177: (1964) 6 एससीआर 666] में भी इस न्यायालय की संविधान पीठ ने "रॉयल्टी" को 'भूमि से प्राप्त सामग्री या खनिजों के लिए किया गया भुगतान' के रूप में परिभाषित किया था।

61. उच्च न्यायालयों में प्रचलित न्यायिक राय पर ध्यान दिया जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य [लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य, 1983 एससीसी ऑनलाइन ओरी 16: एआईआर 1983 ओरी 210: (1983) 55 सीएलटी 362], एससीसी ऑनलाइन ओरी पैरा 12: एआईआर पृष्ठ 224, पैरा 12 '[रॉयल्टी] निकाले गए खनिजों के लिए किया गया भुगतान है। यह कर नहीं है।' [सूरजदीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1959 एससीसी ऑनलाइन एमपी 19: एआईआर 1960 एमपी 129: 1960 एमपीएलजे 39] मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने व्हार्टन लॉ लेक्सिकन और मोजले एवं व्हाइटली लॉ डिक्शनरी का हवाला दिया और कहा (एआईआर पृष्ठ 130, पैरा 7 पर) 'रॉयल्टी वे भुगतान हैं जो सरकार खनिजों, लकड़ी या सरकार से संबंधित अन्य संपत्ति के विनियोग के लिए मांग सकती है।' उच्च न्यायालय ने कहा कि रॉयल्टी की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: (i) भुगतान हटाए गए मात्रा के अनुपात में है; और (ii) भुगतान का आधार एक समझौता है

71. हमने उक्त त्रुटि को स्पष्ट रूप से इंगित किया है, क्योंकि हम इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ऐसा करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और नैतिक रूप से खुद को बाध्य महसूस करते हैं, ताकि उक्त त्रुटि "रॉयल्टी" के अर्थ के इर्द-गिर्द केंद्रित न्यायशास्त्रीय विचार की प्रवृत्ति को और अधिक नुकसान न पहुंचाए। हम मानते हैं कि रॉयल्टी कर नहीं है। रॉयल्टी भूमि के मालिक को दी जाती है जो एक निजी व्यक्ति हो सकता है और जरूरी नहीं कि वह राज्य हो। भूमि का मालिक एक निजी व्यक्ति रॉयल्टी

वसूलने का हकदार है, लेकिन कर नहीं। पट्टाकर्ता अपनी आय के रूप में रॉयल्टी प्राप्त करता है और पट्टेदार के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी एक व्यय है। रॉयल्टी कर नहीं हो सकती। हम घोषणा करते हैं कि इंडिया सीमेंट लिमिटेड [इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी.एन. राज्य (1990) 1 एससीसी 12] में भी न्यायालय का यह निष्कर्ष नहीं था कि रॉयल्टी एक कर है। न्यायालय के किसी निर्णय में स्पष्ट मुद्रण संबंधी या अनजाने में हुई त्रुटि के कारण दिए गए कथन को न्यायालय द्वारा ऐसे कानून की घोषणा के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। हम महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड [राज्य मध्य प्रदेश बनाम महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड, 1995 सप (1) एससीसी 642] में दिए गए निर्णय के उस हिस्से से भी अपनी असहमति दर्ज करते हैं, जिसमें कहा गया है (एससीसी रिपोर्ट के पैरा 12 के अनुसार) कि इंडिया सीमेंट [इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12] में कोई "मुद्रण संबंधी त्रुटि" नहीं थी और यह निष्कर्ष कि रॉयल्टी एक कर है, तार्किक रूप से निर्णय के पहले के पैराग्राफ से अलग है।"

51. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005) 6 एससीसी 499] में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 530-31, पैरा 44-46)

"44. "रॉयल्टी" कानूनी भाषा में बेचे गए माल की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द नहीं है। यह पेटेंट, खदान के पट्टे या इसी तरह के अधिकार के अनुदानकर्ता द्वारा आरक्षित भुगतान है, और अनुदानकर्ता द्वारा अधिकार के उपयोग के अनुपात में देय है जैसा कि टिटागुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड मामले में माना गया है [उड़ीसा राज्य बनाम टिटागुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड, 1985 सप एससीसी 280: 1985 एससीसी (कर) 538]।

45. अपने प्राथमिक और प्राकृतिक अर्थ में कानूनी दुनिया में "रॉयल्टी" को "जुरा रेगलिया" या "जुरा रेजिया" के समकक्ष या अनुवाद के रूप में जाना जाता है। एक संप्रभु के शाही अधिकार और विशेषाधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। अपने द्वितीयक अर्थ में, "रॉयल्टी" शब्द खनन पट्टों की तरह, अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए नकद या वस्तु के रूप में देय रेडेंडम के उस हिस्से को दर्शाता है, जो परिवर्तनशील है। (इंद्रजीत सिंह सियाल बनाम करम चंद थापर [इंद्रजीत सिंह सियाल बनाम करम चंद थापर (1995) 6 एससीसी 166] देखें।)

46. "रॉयल्टी" कोई कर नहीं है। केवल इसलिए कि रॉयल्टी उत्पादित खनिजों की मात्रा के संदर्भ में लगाई जाती है और आरोपित उपकर भी उत्पादित खनिज की समान मात्रा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, बाद वाला रॉयल्टी नहीं बनता है। पहला वह भूमि का किराया है जिस पर

खदान स्थित है या सरकार द्वारा खनन पट्टेदार के पक्ष में छोड़ी गई भूमि से खनिज जीतने के विशेषाधिकार की कीमत है। उपकर खनिज अधिकारों पर लगाया जाने वाला कर है जिसका भूमि पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादित खनिज की मात्रा के संदर्भ में परिमाणित किया जाता है। अंतर, हालांकि ठीक है, फिर भी मौजूद है और बोधगम्य है। (देखें पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एससीसी 201])”

52. कर की आवश्यक विशेषताओं पर, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य [जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) 12 एससीसी 1] में सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति भानुमति की निम्नलिखित टिप्पणियां सार को उजागर करती हैं: (एससीसी पृष्ठ 297, पैरा 334) "334. कर की आवश्यक विशेषताएं हैं: (i) यह करदाता की सहमति के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है और भुगतान कानून द्वारा लागू किया जाता है; (ii) यह करदाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया गया अधिरोपण है; और (iii) यह सामान्य भार का हिस्सा है। कमिश्नर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर ऑफ श्री शिरूर मठ [कमिश्नर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर ऑफ श्री शिरूर मठ, 1954 एससीआर 1005: एआईआर 1954 एससी 282], संविधान पीठ ने कर की विशेषताओं को निर्धारित किया है जिसका तब से लगातार पालन किया जा रहा है और यह इस प्रकार है: (एआईआर पृष्ठ 295, पैरा 43)

'43. ... "कर" ... "सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन की अनिवार्य वसूली है जो कानून द्वारा लागू की जा सकती है और "प्रदान की गई सेवाओं के लिए" भुगतान नहीं है।" यह परिभाषा, सभी की राय में, कर की आवश्यक विशेषताओं को सामने लाती है जो अन्य प्रकार के अधिरोपण से अलग है जो एक सामान्य अर्थ में इसके अंतर्गत आते हैं। यह कहा जाता है कि कराधान का सार मजबूरी है, अर्थात्, यह करदाता की सहमति के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है और भुगतान कानून द्वारा लागू किया जाता है। ...

कर की दूसरी विशेषता यह है कि यह करदाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया गया अधिरोपण है। यह इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि कर का अधिरोपण सामान्य राजस्व के उद्देश्य से किया जाता है, जिसे एकत्र किए जाने पर वह राज्य के सार्वजनिक राजस्व का हिस्सा बन जाता है। चूंकि कर का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को कोई विशेष लाभ प्रदान करना नहीं है, इसलिए जैसा कि कहा जाता है, करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच कोई "क्विड प्रो क्वो" तत्व नहीं है, ... कराधान की एक और विशेषता यह है कि चूंकि यह सामान्य

भार का एक हिस्सा है, इसलिए करदाता पर लगाए जाने वाले कर की मात्रा आम तौर पर उसकी भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है।"

53. यह सच है कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण [खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण (2011) 4 एससीसी 450] में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत निर्धारित "रॉयल्टी" से संबंधित कुछ प्रश्न अब नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजे गए हैं, जो संदर्भ अभी भी विचाराधीन है। हालाँकि, वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं उठता है।

54. एक अनुबंध में "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति के उपयोग पर, हम इंद्रजीत सिंह सियाल बनाम करम चंद थापर [इंद्रजीत सिंह सियाल बनाम करम चंद थापर (1995) 6 एससीसी 166] : (एससीसी पृष्ठ 173, पैरा 12-13) में निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट कर सकते हैं

"12. ... इस प्रकार, विलेख में "रॉयल्टी" शब्द का प्रयोग ढीले अर्थ में किया गया था ताकि पट्टे की अवधि के दौरान असाइनर को आवधिक भुगतान करने की देयता को व्यक्त किया जा सके; भुगतान कोयले की मात्रा या प्रेषण पर निर्भर करता है। इसलिए हमें दस्तावेज़ एक्सटेंशन डी-5 को अपनी शर्तों पर समझना होगा, न कि केवल निर्धारित भुगतानों को दिए गए लेबल या विवरण पर। संभवतः इस व्यवस्था को किसी अन्य शब्द का उपयोग करके आकार दिया जा सकता था। लेखकों के लिए "रॉयल्टी" शब्द शायद इस तरह की व्यवस्था के लिए अधिक सुविधाजनक था, ताकि आवधिक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी स्थिति में पार्टियों को "रॉयल्टी" शब्द का उपयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जैसे कि वे राज्य के शाही या संप्रभु अधिकार को अपने लिए हथिया रहे हों और फिर विलेख द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को निरर्थक बना रहे हों।

13. वस्तु अपने मूल्य से जानी जाती है; उस आवरण से नहीं जिसमें उसे पैक किया गया है। एक व्यक्ति अपने मूल्य के लिए जाना जाता है; अपने मूल्य के लिए नहीं वह जो कपड़े पहनता है। एक भिखारी द्वारा पहने जाने वाले शाही वस्त्र उसे राजा नहीं बना सकते। दस्तावेज़ को उसके शीर्षक से नहीं, बल्कि उसकी विषय-वस्तु से तौला जाता है। किसी को चमक-दमक नहीं, बल्कि उसके मूल्य पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी, हम दस्तावेज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले सही शब्दों के महत्व को कम नहीं करना चाहते। हम जो व्यक्त करना चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि अगर विचार स्पष्ट है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों में उसका अनुवाद, अक्सर गलत हो सकता है। खासकर उस भाषा में जो मातृभाषा नहीं है। वे गलत शब्द विचार को बदलने के लिए वापस नहीं आ सकते। इस प्रकार संक्षेप में और सार रूप में जब अनुबंध करने वाले पक्षों और ड्राफ्ट्समैन को यह पता चल जाता है कि "रॉयल्टी"

शब्द का इस्तेमाल राज्य के लिए राज्य द्वारा दी गई चीजों में से कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है, तो निजी सुरक्षा के लिए उस शब्द का इस्तेमाल असाइनर को संप्रभु या राज्य का दर्जा देने और उस आधार पर दस्तावेज को रद्द करने के लिए नहीं किया गया था।

55. हम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोशन पिक्चर एसोसिएशन] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान दे सकते हैं। (1999) 6 एससीसी 150], जहां शुल्क का भुगतान पार्टियों के बीच एक अनुबंध की शर्तों के तहत किया गया था: (एससीसी पीपी. 169-71, पैरा 31-32)

“31. प्रदर्शकों का यह भी तर्क है कि शुद्ध वसूली पर एक प्रतिशत का शुल्क कर के रूप में एक अनिवार्य वसूली है। न तो अधिनियम और न ही लाइसेंस के प्रावधानों में ऐसे किसी कर का भुगतान निर्धारित है। इसलिए इस राशि का अधिरोपण संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है। यह सच है कि न तो संबंधित अधिनियम और न ही अधिसूचना और न ही नियम और न ही लाइसेंस की शर्तें किसी किराये के भुगतान का प्रावधान करती हैं। इस राशि का भुगतान एक समझौते के तहत किया जाना आवश्यक है जिसे प्रदर्शक व्यक्तिगत रूप से इन फिल्मों की आपूर्ति के लिए फिल्म प्रभाग के साथ करते हैं। यह दो पक्षों के बीच एक अनुबंध की शर्तों के तहत भुगतान है। इसलिए, इसे कर के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। प्रदर्शकों का तर्क है कि क्योंकि उन्हें इन अनुबंधों में प्रवेश करने की आवश्यकता है समझौते के तहत कोई भी भुगतान अनिवार्य वसूली है और इसलिए यह कर है। हम इससे सहमत नहीं हैं। समझौते की शर्तों के तहत फिल्म प्रभाग को निश्चित अंतराल पर थिएटर मालिकों को कुछ प्रिंट देने होते हैं। फिल्म प्रभाग को इस उद्देश्य के लिए वितरण नेटवर्क बनाए रखना होता है। उसे इन फिल्मों को पैक करना होता है और प्रदर्शकों को एक निश्चित अवधि के लिए इन फिल्मों को अपने पास रखने की अनुमति देनी होती है। इसके बाद फिल्मों को फिल्म प्रभाग को वापस करना होता है। समझौते में इस शुल्क को फिल्मों का किराया कहा गया है। इसमें वितरण के लिए फिल्मों के प्रिंट तैयार करने और डिलीवरी के लिए उन्हें पैक करने का शुल्क शामिल है। ये स्पष्ट रूप से फिल्म प्रभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जिसके लिए उसे शुद्ध संग्रह का एक प्रतिशत किराया के रूप में दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, प्रिंट तैयार करने, उन्हें पैक करने और उन्हें वितरित करने की कुल लागत फिल्म प्रभाग द्वारा सभी प्रदर्शकों से किराए के रूप में की गई कुल वसूली से बहुत अधिक है। दी जाने वाली सेवाओं और किए जाने वाले भुगतान के बीच स्पष्ट संबंध है। इसलिए, यह भुगतान कर के बजाय शुल्क की प्रकृति का है, हालांकि इसमें कोई सटीक प्रतिदान नहीं हो सकता है। फिर भी प्रतिदान का तत्त्व बहुत मौजूद है।

32. प्रदर्शकों ने कई मामलों का हवाला दिया जो कर को शुल्क से अलग करते हैं। हम उनमें से कुछ का ही उल्लेख करेंगे। जिला परिषद, जोवाई स्वायत्त जिला बनाम द्वेत सिंह रिंबाई [जिला परिषद, जोवाई स्वायत्त जिला बनाम द्वेत सिंह रिंबाई (1986) 4 एससीसी 38: 1986 एससीसी (कर) 768] में इस न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य वसूली कर के बराबर होगी जबकि प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान शुल्क के बराबर होगा। उस मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं था जो रॉयल्टी को शुल्क के रूप में लगाने को उचित ठहराए। कमिशनर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर [कमिशनर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर, 1954 एससीआर 1005: एआईआर 1954 एससी 282] में इस न्यायालय ने 1954 में ही कर और शुल्क के बीच अंतर निर्धारित कर दिया था। इस न्यायालय ने कर को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक अनिवार्य वसूली के रूप में वर्णित किया है जिसके लिए करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है; जबकि शुल्क कुछ लोगों के लिए विशिष्ट सेवा के लिए एक शुल्क है, और इसका सेवा के लिए किए गए खर्चों से कुछ संबंध होना चाहिए। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावाला [अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावाला (1992) 3 एससीसी 285] में इस न्यायालय ने कहा है कि शुल्क लगाने के लिए एक स्पष्ट प्राधिकरण आवश्यक है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, किराया फिल्म प्रभाग द्वारा फिल्म प्रभाग और व्यक्तिगत प्रदर्शक के बीच एक समझौते के आधार पर लिया जाता है। यह फिल्म प्रभाग द्वारा प्रदर्शक को फिल्में आपूर्ति करने, फिल्म को पैक करने और इसकी डिलीवरी की व्यवस्था करने के विचार में है। यह स्पष्ट रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए लिया जाने वाला एक सहमत शुल्क है। इसे अनिवार्य वसूली या कर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। एक वैधानिक दायित्व है जो प्रदर्शकों पर कुछ फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए डाला जाता है। इस वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए, यदि प्रदर्शक फिल्म प्रभाग के साथ एक समझौता करते हैं और वैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए फिल्म प्रभाग से फिल्में खरीदने के लिए एक निश्चित राशि का किराया देने के लिए सहमत होते हैं, तो शुल्क को, चूंकि यह फिल्म प्रभाग द्वारा अनुबंध के तहत कुछ दायित्वों का निर्वहन करने से संबंधित है, उच्चतम रूप से एक शुल्क के रूप में देखा जाना चाहिए न कि कर के रूप में। बनाम भारत संघ, 1995 एससीसी ऑनलाइन डेल 600: (1995) 60 डीएलटी 180] ने प्रतिवादी प्रदर्शकों के तर्क को सही रूप से नकार दिया है।

56. इस प्रकार, "रॉयल्टी" शब्द को हमेशा अनुदानकर्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के रूप में समझा जाता है और आम तौर पर अनुदानकर्ता और

अनुदानकर्ता के बीच किए गए समझौते में इसकी उत्पत्ति होती है। कर के विपरीत, जो करदाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है, रॉयल्टी पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार होगी और आम तौर पर अनुदानकर्ता को दिए जाने वाले लाभ या विशेषाधिकार के साथ इसका सीधा संबंध होता है।

3. 11. सार्वजनिक निकाय निजी व्यक्तियों की तरह ही तथ्यों और वादों के अभ्यावेदन को पूरा करने के लिए बाध्य हैं, जिन पर भरोसा करके अन्य व्यक्तियों ने उनके प्रति पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी स्थिति बदल ली है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन से उत्पन्न होने वाला दायित्व, जो कि एक वादा है, उस व्यक्ति द्वारा अनुबंधों के माध्यम से लागू किया जा सकता है जो उस वादे पर कार्य करता है: जब कानून की आवश्यकता होती है कि किसी सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध कानून के तहत लागू होने वाला अनुबंध निश्चित रूप में होगा या कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निष्पादित किया जाएगा, तो यदि अनुबंध उस रूप में नहीं है तो दायित्व को उचित मामलों में इक्विटी में उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है। भारत संघ बनाम इंडो-अफगान एजेंसीज लिमिटेड [(1968) 2 एससीआर 366] में इस न्यायालय ने माना कि सरकार नागरिकों द्वारा उनके प्रति पक्षपातपूर्ण तरीके से किए गए कार्यों से उत्पन्न इक्विटी से मुक्त नहीं है, जो कि सरकार द्वारा अपने भविष्य के आचरण के बारे में किए गए अभ्यावेदनों पर निर्भर करता है। इस न्यायालय ने माना कि रॉबर्टसन बनाम पेंशन मंत्री [(1949) 1 केबी 227] में डेनिंग, जे. द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ भारत में लागू होती हैं:

"क्राउन यह कहकर बच नहीं सकता कि एस्टॉपेल्स क्राउन को बाध्य नहीं करते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का बहुत पहले ही खंडन किया जा चुका है। न ही क्राउन कार्यकारी आवश्यकता के सिद्धांत की सहायता के लिए प्रार्थना करके बच सकता है, अर्थात्, यह सिद्धांत कि क्राउन अपने भविष्य के कार्यकारी कार्यों को बाधित करने के लिए खुद को बाध्य नहीं कर सकता है।" इस मामले में हम इस सवाल से निपटने के लिए चिंतित नहीं हैं कि क्या डेनिंग, एल.जे., नियम को अलग-अलग श्रेणी के मामलों में विस्तारित करने में सही थे, जैसा कि फालमाउथ बोट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम हॉवेल [(1950) 1 ऑल ईआर 538] में उन्होंने पृष्ठ 542 पर देखा:

"जब भी सरकारी अधिकारी किसी विषय के साथ अपने व्यवहार में उस विषय से संबंधित मामले में अधिकार ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो वह इस बात पर भरोसा करने का हकदार है कि उनके पास वह अधिकार है जिसे वह ग्रहण करते हैं। वह नहीं जानता है, और न ही उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह उनके अधिकार की सीमाओं को जाने, और यदि वे इसे पार करते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं उठाना चाहिए।"

यह देखना पर्याप्त हो सकता है कि उस निर्णय (हॉवेल बनाम फालमाउथ बोट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) से अपील में लॉर्ड सिमंड्स ने डेनिंग, एल.जे. की टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद कहा:

"किसी कार्य की अवैधता एक समान है, चाहे वह सरकारी अधिकारी की ओर से अधिकार की धारणा द्वारा गुमराह किया गया हो, चाहे वह पदानुक्रम में उच्च या निम्न हो।

XXX

सवाल यह है कि क्या वैधानिक निषेध के तहत किए गए कार्य का चरित्र इस तथ्य से प्रभावित होता है कि यह अधिकार की भ्रामक धारणा से प्रेरित था। मेरी राय में इसका उत्तर स्पष्ट रूप से है: नहीं।"

4. '10. यह अवलोकन, "स्पष्ट रूप से बहुत व्यापक है और इसका उचित दायरा निर्धारित करना कठिन है": एन्सन का अनुबंध का अंग्रेजी कानून, 22 वां संस्करण, पृष्ठ 174. यह भी ध्यान देने योग्य है कि रॉलेट, जे. के समक्ष, आवेदकों ने क्राउन के खिलाफ एक अनुबंध के प्रवर्तन का दावा किया था, और विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई अनुबंध नहीं था और कोई हर्जाना नहीं दिया जा सकता था। रॉबर्टसन बनाम पेंशन मंत्री [(1949) 1 केबी 227] डेनिंग, जे. ने पृष्ठ 231: पर अवलोकन किया।

"क्राउन यह कहकर बच नहीं सकता कि एस्टॉपेल क्राउन को बाध्य नहीं करते क्योंकि उस सिद्धांत का बहुत पहले ही खंडन हो चुका है। न ही क्राउन कार्यकारी आवश्यकता के सिद्धांत की सहायता के लिए प्रार्थना करके बच सकता है, अर्थात्, वह सिद्धांत कि क्राउन अपने भविष्य के कार्यकारी कार्यों को बाधित करने के लिए खुद को बाध्य नहीं कर सकता। उस सिद्धांत को रॉलेट, जे. ने रेडेरियाक्टीबोलागेट एम्फीट्राइट बनाम किंग में प्रतिपादित किया था, लेकिन यह निर्णय के लिए अनावश्यक था क्योंकि कथन में कोई वादा नहीं था जो बाध्यकारी होने का इरादा रखता था, बल्कि केवल इरादे की अभिव्यक्ति थी। रॉलेट, जे. क्राउन के अपने सेवकों को अपनी मर्जी से बर्खास्त करने के अधिकार पर मामलों से प्रभावित प्रतीत होते हैं, लेकिन उन सभी मामलों को अब लॉर्ड एटकिन के रेली बनाम किंग [(1954) एसी 176, 179] के फैसले के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। ... मेरी राय में कार्यकारी आवश्यकता का बचाव सीमित दायरे का है। यह क्राउन को तभी लाभ पहुंचाता है जब कोई निहित हो उस प्रभाव के लिए शब्द या जो अनुबंध का सही अर्थ है।"

डेनिंग, जे., एक सेवारत सेना अधिकारी के मामले से निपट रहे थे, जिसने विकलांगता के बारे में युद्ध कार्यालय को लिखा था और उसे जवाब मिला कि उसकी विकलांगता को "सैन्य सेवा" के कारण माना गया है। उस आश्वासन पर भरोसा करते हुए उसने एक स्वतंत्र चिकित्सा राय प्राप्त करने से परहेज किया। पेंशन मंत्री ने बाद में फैसला किया कि अपीलकर्ता की विकलांगता को युद्ध सेवा के कारण नहीं

माना जा सकता। यह माना गया कि विषयों के बीच ऐसा आश्वासन लागू करने योग्य होगा क्योंकि इसका उद्देश्य बाध्यकारी होना था, जिस पर कार्रवाई की जानी थी, और वास्तव में उस पर कार्रवाई की गई थी; और यह आश्वासन क्राउन पर भी बाध्यकारी था क्योंकि कोई भी शर्त निहित नहीं हो सकती थी कि क्राउन इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र था।

24. हमारे न्यायशास्त्र के तहत सरकार अपने भविष्य के आचरण के बारे में अपने द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं है और वह आवश्यकता या समीचीनता के किसी अनिर्धारित और अधोषित आधार पर अपने द्वारा किए गए वचन को पूरा करने में विफल नहीं हो सकती है, न ही वह उन परिस्थितियों के एकपक्षीय मूल्यांकन पर नागरिक के प्रति अपने दायित्व का न्यायाधीश होने का दावा कर सकती है जिनमें दायित्व उत्पन्न हुआ है। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि वस्त्र आयुक्त द्वारा पारित और केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि किए गए विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और वस्त्र आयुक्त तथा आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे प्रतिवादियों को उनके द्वारा निर्यात किए गए माल के एफओबी मूल्य के 100% के बराबर कुल राशि के लिए आयात प्रमाण पत्र जारी करें, जब तक कि कोई ऐसा निर्णय न हो जो संबंधित योजना के खंड 10 के अंतर्गत विफल हो।

5. '146. विज्ञापन के प्रयोजन के लिए स्थल के उपयोग के लिए लाइसेंस।-(1) लाइसेंस की ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन और उनके अनुरूप, जैसा कि नगरपालिका विनियमों द्वारा प्रदान कर सकती है, कोई भी व्यक्ति जो स्वामी, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, अधिभोगी या विज्ञापन एजेंट है, किसी भी भूमि, भवन या दीवार में किसी स्थल का उपयोग नहीं करेगा, या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, या किसी भी स्थल पर किसी भी विज्ञापन के प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए कोई होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट, कियोस्क, संरचना, वाहन, नियोन-साइन या स्काई-साइन नहीं लगाएगा, या लगाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) विज्ञापन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी स्थल का उपयोग, ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, या

(ख) किसी स्थल का उपयोग करने का इरादा रखता है, या

(ग) जिसका किसी स्थल के उपयोग के लिए लाइसेंस समाप्त होने वाला है। लाइसेंस या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, जैसा भी मामला हो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आवश्यक निरीक्षण करने के बाद और आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, विनियमों द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस प्रदान या नवीनीकृत करेगा या लाइसेंस को अस्वीकार या रद्द कर देगा, जैसा भी मामला हो।

(4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, यदि उसकी राय में, किसी विज्ञापन के लिए प्रस्तावित स्थल सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात के खतरों या सौंदर्य डिजाइन के विचारों से अनुपयुक्त है, तो आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर लाइसेंस देने या किसी मौजूदा लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार कर सकता है।

(5) प्रत्येक लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, सिवाय उन स्थलों के जो मेले, त्योहार, सर्कस, यात्रा, प्रदर्शनियों, खेल आयोजनों या सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों सहित किसी भी प्रकृति के अस्थायी समागम के लिए उपयोग किए जाते हैं।

(6) मुख्य नगरपालिका अधिकारी एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें इस धारा के तहत जारी लाइसेंसों को विज्ञापन स्थलों के संबंध में अलग से दर्ज किया जाएगा-

(क) टेलीफोन, टेलीग्राफ, ट्राम, बिजली या अन्य खंभों या खंभों पर जो सार्वजनिक या निजी सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर या उनके किनारे स्थापित किए गए हों,

(ख) भूमि या भवनों में, और

(ग) सिनेमा हॉल, थियेटर या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थानों में।

6. '431. अध्याय XVII के तहत कर का भुगतान न करने पर जुर्माना.- यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन को उस अध्याय के तहत कोई कर चुकाए बिना लगाता है, प्रदर्शित करता है, स्थापित करता है या रखता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ऐसे कर के दो गुना के बराबर राशि से कम नहीं होगा और ऐसे कर के रूप में देय राशि के पांच गुना के बराबर राशि तक बढ़ाया जा सकता है।'

7. इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड (सुप्रा) का पैराग्राफ 57

8 गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (1990) 2 एससीसी 71

9 (2005) 6 एससीसी 499

10 इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड (सुप्रा)

11 [1989] सप्लीमेंट 1 एससीआर 692: (1990) 1 एससीसी 12.